Mahila College Dalmianagar
Department of History
B.A.-III (Hons)

Dr. Anu Kumari
Date:- 10/02/2020

Q:- कृषि का वाणिज्यीकरण :- कारण तथा परिणाम

=> ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। कृषि के वाणिज्यीकरण का तात्पर्य उत्पादन की ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कृषि उत्पादों का प्रयोग व्यापारिक मुनाफे के लिए किया जाता है। यह एक धीमी विकास की प्रक्रिया थी। जिसे पूर्व औपनिवेशिक काल में भी देखा गया। औपनिवेशिक काल में यह प्रक्रिया अधिक तेज हुई तथा इसकी संरचना में परिवर्तन हुए। मुगल काल में वाणिज्यीकरण के प्रेरित करने वाले तत्व राजस्व का दबाव अथवा लगभग 15% शहरी आबादी के उपयोग की आवश्यकता थी, किंतु औपनिवेशिक सरकार ने स्वहितार्थ वाणिज्यीकरण को नियंत्रित एवं अंततः आरोपित किया। इस प्रकार पूर्वकाल में जहाँ कृषि अधिशेषों की बिक्री होती थी वहीं अब बिक्री हेतु उत्पादन होने लगा। भारत में इस नियोजित

वाणिज्यीकरण की औपनिवेशिक नीति के प्रतिकूल प्रभाव हुए।
अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नई लगान नीति के कारण किसान को अब नकद राशि की आवश्यकता थी इसीलिए किसान उन फसलों को उगाने के लिए मजबूर होने लगे जिनका बाजार में क्रय-विक्रय हो सके।

1850 के बाद ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा संचित पूंजी के निवेश की चिंता ने भारत में वाणिज्यिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया।

कंपनी का चीन के साथ व्यापार के सन्दर्भ में व्यापारिक संतुलन चीन के पक्ष में था। इसके समाधान के तौर पर उसने भारत में चाय की खेती पर बल दिया ताकि चीन से होनेवाले चाय के आयात को कम किया जा सके। इसी प्रकार भारत से अफीम निर्यात के द्वारा व्यापारिक संतुलन लाने की कोशिश की गयी।

कपास, चाय, कॉफी, अफीम, जूट आदि प्रमुख वाणिज्यिक फसलें थीं जिसे अंग्रेजों ने क्षेत्र विशेष के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बढ़ावा दिया था। जैसे - महाराष्ट्र, बंगाल में जूट उत्पादन, कर्नाटक में कॉफी असम में चाय तथा अफीम के व्यापार हेतु पोस्त की खेती को बनारस, बिहार, बंगाल मालवा में बढ़ावा दिया गया। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को अग्रिम धनराशि देने का प्रावधान किया, सिंचाई सुविधाएँ विस्तृत की तथा प्रांतीय स्तर पर लोक निर्माण के विभाग की स्थापना की। 19 वीं सदी के द्वितीयार्द्ध में रेलवे की स्थापना से इस प्रक्रिया को काफी बल मिला। भारत में रेलों का जाल इस प्रकार बिछाया गया कि सुदूरवर्ती ग्रामीण उत्पादन क्षेत्र नजदीकी निर्यात केन्द्रों तथा बंदरगाह से जुड़ जाये।

इस प्रकार कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में एक स्वतंत्र न होकर नियंत्रित प्रक्रिया थी, जिसमें कम्पनी सरकार ने सक्रिय रुचि ली। यह मात्र राजस्व दबावों एवं शहरी आवश्यकताओं के मद्देनजर विकसित नहीं हो रहा था बल्कि निर्यात का तत्व इससे जुड़ा था।

ऐसे में नियंत्रित वाणिज्यीकरण की नीति से भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। यह निर्यातोद्देश्य था और चूंकि इन निर्यातों के बदले भारत कोई आयात प्राप्त नहीं हो रहा था इसलिए इससे धन के अपवाह की प्रक्रिया जुड़ गई।

वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्माधित्व का संकट पैदा किया। भारतीय कृषि जगत एवं इससे जुड़ा सामंत तंत्र पूंजीवादी अर्थनीति के विश्वव्यापी तंत्र के एक पुर्जे के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार भारतीय कृषक को एक दूरस्थ एवं अपरिचित विदेशी बाजार पर आश्रित बना दिया गया जिनके साथ उसका एकमात्र संबंध बिचौलिया की एक सशक्त श्रृंखला के माध्यम से था। ये बिचौलिए अपने मुनाफे के लिए किसानों का जमकर शोषण करते थे। मूल्यों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का भार भी अंततः किसानों को वहन करना पड़ता था। दरअसल भारतीय कृषक प्राकृतिक आपदाओं के अलावे – महाजन, अधिकारी एवं

एवं व्यापारी वर्ग की तिकड़ी द्वारा जब्त किया गया। नवीन तथा विशिष्ट उपायों की अधिकाधिक पूर्ति हेतु अधिक विनियोग की आवश्यकता ने उसे ऋण लेने का विवश किया। यही नहीं गरीब कृषकों ने जिन्होंने अपनी समस्त जमीन पर नकदी फसल उपजाए उन्होंने उपभोग - ऋण भी लिया जो हमेशा दोगुनी - तिगुनी ब्याज दरों पर मिलता। कृषक इस प्रक्रिया में पिसता हुआ दरिद्र होता गया किंतु उसके पास इससे निकलने का कोई चारा न था। समस्त मशीनरी उसके दमन हेतु तैयार थी। कृषकों को मजबूरन वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया से जुड़ना पड़ता था चाहे वह ऋण का भार हो या लगान चुकाने की मजबूरी। कोयम्बटूर के किसान ने कलक्टर से शिकायत की थी कि वे कपास की खेती केवल इस कारण से करते हैं कि वे कपास खा नहीं सकते। अन्न तो खाने पर समाप्त हो जाता परंतु कपास उगाने पर आधे पेट रहने पर भी लगान तो चुक जाता है। इस प्रकार अधिकांश कृषकों के लिए यह प्रकार का आरोपित वाणिज्यीकरण ही था, स्वैच्छिक या स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं। इंग्लैंड के कृषकों के विपरीत इसका समस्त लाभ किसानों के बजाये ब्रिटिश सरकार को मिला।

कृषि के वाणिज्यीकरण में फसलें प्रायः औद्योगिक आवश्यकताओं (ब्रिटेन) को ध्यान में रखकर उगाई जाती थी फलतः खाद्यान्नों के बजाये नकदी फसलों की खेती ने अकाल एवं दुर्भिक्ष को आमंत्रित किया जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्राक् - ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकालों की

मुख्य वजह अधिक प्राकृतिक तथा ब्रिटिश ग्राम यातायात के साधनों का अभाव था किंतु ब्रिटिश काल में इसके पीछे औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियां काम कर रही थी।

न्याय नील, चाय तथा नकदी फसलों का नियंत्रण यूरोपीय बागान मालिकों के हाथ में था। इसमें श्रमिकों की भर्ती इर-इकरार के झांसो से अनुबंध पद्धति के द्वारा की जाती थी जिनमें उनकी स्थिति दासों के समान हो गई।

वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया का सारा लाभ बिचौलियों को मिला था कि उन किसानों को जो उत्पादक थे। इससे सामाजिक संरचना में असमानता की खाई चौड़ी हुई जिसकी कीमत पर वाणिज्यीकरण हुआ वे अंतत: दरिद्र ही बने रहे।

कृषि के वाणिज्यीकरण का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इसने क्षेत्रीय विशिष्टीकरण को जन्म दिया। विशेष क्षेत्र में विशेष फसल उत्पादन से विशेषीकृत क्षेत्र का विकास हुआ। कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ। इसके प्रभाव से उच्चस्तरीय सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं का विकास हुआ।

वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति, शहरी सम्पर्क बढ़ा, अर्थव्यवस्था एकीकृत हुई। इसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का आधार तैयार किया।

ग्राम - नगर सम्बन्ध वैश्वीकरण एवं पूंजीवाद के आरम्भ से अर्थव्यवस्था का मुद्राकरण हो गया जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आई।

वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग का शोषण हुआ पर यह समस्त प्रक्रिया भारत में राष्ट्रवाद के आगमन में सहायक सिद्ध हुई। किसानों ने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठायी जिससे विभिन्न कृषक विद्रोह हुये। इससे भारतीय कृषक वर्ग के सुप्त होने की पारम्परिक अवधारणा टूटी।

कुल मिलाकर कृषि का वाणिज्यीकरण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से परिचालित था अतः इसका लाभ मुख्यतः अंग्रेजों को मिला। यह एक आरोपित प्रक्रिया थी जिसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। इसके कतिपय सकारात्मक प्रभाव ब्रिटिश नीतियों का हिस्सा न था यह लाभ भी हानि की तुलना में नगण्य था।